





# शिकायत अटेंड किए बगैर आगे बढ़ी तो संबंधित अधिकारी का कटेगा वेतन : कलेक्टर श्रीमती चौहान सीएम हैल्पलाइन की शिकायतों की हुई समीक्षा



जवालियर (ए.)। सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण विभाग के खिलाफ कार्रवाई के लिये भेजा प्रस्ताव कोई भी शिकायत अटेंड किए गए न बढ़े, संतुष्टिपूर्ण निराकरण हो और 50 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों का निराकरण समयबद्ध कार्यक्रम के तहत करें। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्रीमती चौहान ने सीएम हैल्पलाइन पोर्टल पर आई शिकायतों की समीक्षा के दौरान विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत एल-1 स्तर पर अटेंड नहीं की गई तो संबंधित अधिकारी का

साथ दिन का वेतन काटा जायेगा। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने जनजाति कल्याण विभाग की शिकायतों के निराकरण की स्थिति ठीक न पाए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने सहायक आयुक्त जनजाति कल्याण विभाग के खिलाफ कार्रवाई के लिये संभाग आयुक्त को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही वेतन रोकने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की सहायताथर्थ संचालित संकटपत्र योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को तपत्तर से दिलाया जाए। साथ ही आवास भत्ता का लाभ पात्र विद्यार्थियों

को समय-सीमा के भीतर दिलाना सुनिश्चित करें। सीएम हैल्पलाइन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्रीमती चौहान ने फसल बीमा संबंधी शिकायत के निराकरण में उदासीनता सामने आने पर भिरवार के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को वेतन काटने का कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश उप संचालक कृषि को दिए। साथ ही निर्देश किया गया कि जिन अधिकारियों ने द्वारा सीएम हैल्पलाइन की शिकायतें समय-सीमा के भीतर अटेंड नहीं की जा रही हैं, उनको विधिवत नोटिस जारी करें और सही जवाब न होने पर 7 - 7 दिवस का वेतन काटें। बैठक में खासीतर पर उन विभागों की सीएम हैल्पलाइन के निराकरण की समीक्षा की गई, जो शिकायतों के निराकरण के लिया जाने के साथ-साथ आयुक्त के साथ-साथ संबंधित संकटपत्र योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को तपत्तर से दिलाया जाए। बुधवार की साथ कलेक्टर के सभागार में आयोजित हुई बैठक में अपने जिला दण्डनाधिकारी टी एन सिंह व संयुक्त कलेक्टर संजीव जैन सहित जिले के एसडीएम व विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी माजूद थे।

## किसान भाई उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण करें

रत्नाम, (आरएनएस)। प्रदेश शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय द्वारा अग्रिम भण्डारण की योजना लागू की गई है। उक्त योजना 31 मई तक लागू रहेगी। किसान भाई आवश्यकतानुसार रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण करें। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्रीमती चौहान ने बताया कि वर्षमान में यूरिया 6294, डीएपी 1492, पोटाश 1257 तथा काम्पलेक्स 6425 मैट्रिक्ट टन उपरांत संबंधितों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का प्रारूप रासायनक खाद का मात्र जिले में भण्डारण है। खरीफ वर्ष 2025 में किसानों को रासायनिक उर्वरकों की अत्यधिक आवश्यकता होगी। किसान भाई योजना का लाभ लेते हुए अग्रिम भण्डारण कर लें, ताकि किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

## एक प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं दो शिक्षकों को किया बहाल

दतिया (ए.)। पदन अपर संचालक लोक शिक्षण एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला संचायत अक्षय कुमार तेप्रवाल ने वित्त दिवस जिला दतिया के बसई के विभिन्न माध्यमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं दो प्राथमिक शिक्षक बिना सूचना के अनुपस्थित पाए जाने के कारण संबंधित को कार्यालयीन आदेशानुसार निलंबित किया गया था। परीक्षण उपरांत संबंधितों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का प्रारूप रासायनक शासकीय कन्व्या मा. विद्यालय वर्सड के प्रभारी प्रधानाध्यापक लव कुमार योगी, प्राथमिक शिक्षक श्रीमती कुमुम साहू, शासकीय मा. कन्व्या विद्यालय वर्सई प्राथमिक शिक्षक श्रीमती किरण गुप्ता का एक-एक दिवस का वेतन काटते हुए यथावत बहाल किया गया है। निलंबन अवधि सभी प्रयोजनों के लिए मात्य होगी।

## गुड न्यूज़ : अब चलती ट्रेन में भी यात्री निकाल सकें, रेलवे ने शुरू की एटीएम सुविधा

नई दिल्ली (आरएनएस)। अक्सर लंबी दूरी की यात्रा के दौरान नकदी की कमी महसूस होती है। यात्रियों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए भारतीय

रेलवे ने एक अनुरूप पहल की है। अब ट्रेन में सफर करने वाले यात्री भी आसानी से ड्यूसे पैसे निकाल सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए चलती ट्रेन में ड्यूल सेवा शुरू करने की तैयारी कर ली है और फिलाहाल इसका द्वायल किया जा रहा है रेलवे ने इस सुविधा को प्रायोगिक तौर पर अनुसार एक्सप्रेस में एक एटीएम मरीन लगाई गई है, जिससे यात्री अपनी यात्रा के दौरान ही नकदी निकाल सकेंगे वह नई सुविधा उन यात्रियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगी जो ऑनलाइन भूगतान के बायाक नकद में लेनदेन करते हैं। साथ ही, उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिन्हें ट्रेन में ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा न होने या नकदी खत्म हो जाने के कारण असुविधा होती थी। अब उन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसे निकालने के लिए स्टेशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे अधिकारी इस द्वायल के दौरान यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि चलती ट्रेन में ड्यूल मरीन सुचारू रूप से काम करे। नेटवर्क कॉर्पोरेशनी, सुक्ष्म, गोपनीयता, यात्रियों की सुविधा और अन्य आवश्यक पहलों पर बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है।

## ब्रिजस्टोन इंडिया ईवी-डेंगी ट्रायरों के साथ बाजार विस्तार की तैयारी में

नई दिल्ली (आरएनएस)। ब्रिजस्टोन इंडिया, यात्री और वाणिज्यिक वाहनों के लिए टायर निर्माता कंपनी, अपनी दस्युंजा और इयूटूर ऑल टेरेन (A/T) 002 टायर श्रृंखला का विस्तार करने के लिए तैयार है। कंपनी विभिन्न वाहनों की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए इन लोकप्रिय श्रेणियों में एक आकार पेश करेगी।

कंपनी के कार्यकारी निदेशक राजर्षि मोद्द्रा के अनुसार, दस्युंजा 61 टायर एस्प्रीवी, सीयूरी, सेडान और हैंचेवेक जैसे वाहनों के लिए इडिज़ाइन किया गया है और वर्तमान में 14 से 20 इंच के आकार में उपलब्ध है। वहाँ, इयूटूर A/T 002 विशेष रूप से 4X4 वाहनों के लिए बनाया गया है।

मोद्द्रा ने बताया कि कंपनी ने पिछले साल इन श्रेणियों में बुधु कार्यकारी निदेशक राजर्षि मोद्द्रा के अनुसार, दस्युंजा 61 टायर एस्प्रीवी, सीयूरी, सेडान और हैंचेवेक जैसे वाहनों के लिए इडिज़ाइन किया गया है और वर्तमान में 14 से 20 इंच के आकार में उपलब्ध है। वहाँ, इयूटूर A/T 002 विशेष रूप से 4X4 वाहनों के लिए बनाया गया है।

मोद्द्रा ने बताया कि कंपनी ने पिछले साल इन श्रेणियों में बुधु कार्यकारी निदेशक राजर्षि मोद्द्रा के अनुसार, दस्युंजा 61 टायर एस्प्रीवी, सीयूरी, सेडान और हैंचेवेक जैसे वाहनों के लिए इडिज़ाइन किया गया है और वर्तमान में 14 से 20 इंच के आकार में उपलब्ध है। वहाँ, इयूटूर A/T 002 विशेष रूप से 4X4 वाहनों के लिए बनाया गया है।

## अमेरिका से तनातनी बढ़ी : चीन ने बोइंग विमानों की डिलीवरी रोकी, एयरलाइनों को नए विमान न खरीदने के निर्देश



नई दिल्ली (आरएनएस)। अमेरिका और चीन अपनी सभी एयरलाइनों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अब बोइंग से न तो कोई नया विमान खरीदें और न ही अमेरिका से विमानों के लिए बोइंग विमान खरीदाना। अमेरिका के लिए एक गंभीर चुनौती में रहता है कि वे अपनी जानकारी के सम्बन्ध में बोइंग को अवृद्धि करना चाहते हैं। चीन ने अपनी सभी एयरलाइनों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अब बोइंग से न तो कोई नया विमान खरीदें और न ही अमेरिका से विमानों से जुड़े उपकरण या कलर्पूंज मंगाएं।

यह कड़ा कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी सरकार ने पर लिया गया है। इसके साथ ही, चीनी विमानों को निर्देश दिया गया है कि वे अब बोइंग से न तो कोई नया विमान खरीदें और न ही अमेरिका से विमानों से जुड़े उपकरण या कलर्पूंज मंगाएं।

गढ़करी ने स्पष्ट किया कि नई प्रणाली के तहत फिजिकल टोल बूथ की आवश्यकता नहीं होगी। इसके टैरिफ वार के जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर 125 प्रतिशत तक का जबाबी शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इन नए शुल्कों के कारण अमेरिका से आवास वाले विमानों और उनके पार्ट्स की लागत चीन में दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है, जिससे चीनी एयरलाइनों के लिए बोइंग विमान खरीदाना और संचालित करना आर्थिक रूप से एक बोइंग की अवृद्धि के बर्दाफ़े है। चीन के लिए फिजिकल टोल बूथ का सामान करना चाही दी गई है, जिसके लिए एक गंभीर चुनौती में रहता है। चीन का यह फेसला बोइंग के लिए एक गंभीर चुनौती में रहता है, क्योंकि जन दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते विमान बाजारों में से एक है। अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में वैश्विक विमानों की कुल मांग का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा अकेले चीन से आएगा। साल 2018 में बोइंग ने जितने विमान बेचे थे, उनमें से कोरिंब एक-चौहाई (25%) चीन को ही डिलीवर किए गए थे।

गड़

# नये वक्फ कानून से विक्रम किसे है

राधा रमण

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 8 अप्रैल को देशभर में वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। वक्फ संशोधन विधेयक को पिछले सप्ताह संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई थी। हालांकि इस कानून को कई मुस्लिम संगठनों और राजनेताओं ने अल्पसंख्यक हितों के खिलाफ बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी है। देश के अलग-अलग भागों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर कांग्रेस समेत देश के विपक्षी दल इसके विरोध को हवा दे रहे हैं। इस कानून के विरोध में याचिका दाखिल करनेवालों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के प्रतिनिधि समेत 12 लोग शामिल हैं। उधर, केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर मांग की है कि मामले की सुनवाई की पूर्व सूचना उसे भी दी जाए ताकि समय रहते वह भी अपना पक्ष रख सके। इस बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशभर में 'वक्फ बचाव अभियान' शुरू कर दिया है। इसके तहत एक करोड़ लोगों का हस्ताक्षर कराकर प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। यह अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आविर इस कानून में क्या है जिससे मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों का 'इस्लाम' खतरे में आ गया है।

दरअसल, विपक्ष और नये वक्फ कानून का विरोध करनेवालों का कहना है कि सारा विवाद वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों पर कब्जे को लेकर है। देशभर में वक्फ बोर्डों के पास 9.4 लाख एकड़ की जमीन है। इससे ज्यादा भूमि का स्वामित्व रेलवे और सशस्त्र बलों के पास है। वक्फ बोर्डों के पास यह सम्पत्तियां मुसलमानों द्वारा दान की गई हैं, जिन पर दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसा, दुकान आदि स्थापित हैं। इसके अलावा बहुतेरी कृषि भूमि भी है। इसकी देखरेख के लिए देश के हर राज्य में वक्फ बोर्ड गठित किया गया है। समय-समय पर इन वक्फ बोर्डों पर आर्थिक घपले के आरोप लगाये जाते रहे हैं लेकिन चूंकि वक्फ मामलों की सुनवाई सरिया कानून के तहत होने, वक्फ के फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकते और सार्वजनिक अदालतों में नहीं होने के कारण कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। उधर वक्फ बोर्डों के पदाधिकारी मालामाल होते रहे हैं नये वक्फ कानून से आम मुसलमानों को कोई कठिनाई नहीं आएगी। वैसे भी वक्फ ने अपनी आमदनी का उपयोग किसी गरीब मुसलमान की पढ़ाई-लिखाई अथवा उसका जीवनस्तर सुधारने के लिए

किया हो इसका उदाहरण नहीं मिलता। काश, अगर वक्फ बोर्ड मुसलमानों की दशा-दिशा सुधारने की कोई पहल करता होता तो आज हालात कुछ और होते। हां, वक्फ बोर्डें पर काबिज लोग जीवनभर ऐशोआराम का जीवन जरूर जीते रहे (संसद में वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजू ने बताया कि वक्फ बोर्डें के पास लाखों करोड़ की सम्पत्ति होने के बावजूद इसका इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के पक्ष में नहीं होने के कारण अराजकता की स्थिति थी)। हम बिल नहीं लाते तो वह संसद भवन पर भी दावा कर सकते थे। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि नये बिल से अब वक्फ के आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। पहले वक्फ का फैसला ही अंतिम होता था। यह गलत धारणा है कि नया वक्फ कानून मुसलमानों के धार्मिक आचरण, उनके द्वारा दान की गई सम्पत्ति में हस्तक्षेप करेगा। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी कहते हैं कि देशभर में वक्फ का दुरुपयोग करना एक बीमारी बन गई है। इसे रोकने में नया कानून कारगर होगा। आरिफ साहब कहते हैं कि गरीबों, कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों पर अपनी आमदनी में से खर्च करने की बात कुरआन में भी लिखी गई है। लेकिन वक्फ यह सब कहां करता था। वक्फ के जरिये न तो कोई अस्पताल चलता है न ही बढ़िया स्कूल-कालेज। इसके जिमेदारों ने वक्फ को हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इसलिए वक्फ की जमीन पर धर्मार्थ काम करने की ज़रूरत है। उधर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि यह कानून मुसलमानों की सम्पत्ति हड्डपने के लिए बनाया गया है। यह भारत के मूल विचारों पर हमला है। कांग्रेस इसका विरोध करेगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए इतेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष संसद असदुद्दीन

ओवैसी का कहना है कि भाजपा मस्जिद- मन्दिर में टकराव बढ़ाकर देश को अस्थिरता में धकेलना चाहती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि वह पश्चिम बंगाल में कानून को लागू नहीं होने देंगे। मुंगेरीलाल की तरह हसीन सपने देखते हुए बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वह इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। सपा-बसपा के नेता भी कुछ इसी तरह की बात कहते हैं। मुझे कहने दीजिए कि विषय के नेता वक्फ कानून का विरोध कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के हमदर्द बनने का दिखावा कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सर्विधान के अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया था। ये वही लोग हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ पर चुप रहते हैं। ये वही लोग हैं जो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या आदि पर सड़क पर निकल कर विरोध करना भूल गए हैं। ये वही लोग हैं जो समाज में जातीयता का जहर घोलने पर आमादा हैं। ये वही लोग हैं जो जाने-अनजाने भाजपा की बनाई बिसात पर चौसर खेलने को अधिशस हैं दरअसल, भाजपा तो शुरू से चाहती है कि देश का जनमत हिन्दू-मुस्लिम में विभाजित हो जाए ताकि उसे आसानी से बहुमत मिलता रहे। सबाल नये वक्फ कानून पर नहीं, बल्कि कानून बनाने के समय पर होना चाहिए। 2014 और 2019 में जब भाजपा को संसद में पूर्ण बहुमत था। उस समय भाजपा चाहती तो यह कानून आसानी से बनाया जा सकता था। लोकिन तब भाजपा ने ऐसा नहीं किया। अब जबकि लोकसभा में भाजपा के महज 240 सांसद हैं तब यह कानून बनाकर भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंशुप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुख्या चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी, हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार सरीखे अपने सहयोगी दलों के नेताओं की मुस्लिम परस्ती को खुलेआम चुनौती दे दिया है। साथ ही यह संदेश भी कि 'वृद्धावन में रहना है तो राधे-राधे कहना होगा'। बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होनेवाले हैं। इसका सर्वाधिक नुकसान नीतीश की पार्टी जनता दल (यू.), चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) और जीतनराम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा को होगा। भाजपा ने अपने चक्रव्यूह में इन्हें घेर लिया है और निकलने का इनके पास कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। वक्फ बिल पर संसद में जनता दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीवरंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की दलील सुनकर जदयू में भगदड़ की स्थिति बन गई और उसके दर्जनभर से अधिक नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कई अभी पार्टी छोड़ने की कगार पर बैठे हैं और उचित समय का इंतजार कर रहे हैं।

राष्ट्र और मानवता के कल्याण हेतु धर्मानुकूल आचरण को अनिवार्य मानते हैं मोहन भागवत

कृष्णमोहन झा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गत दिवस गुजरात के वलसाड जिले के धरमपुरा में स्थित सदगुर धाम में श्री भावभावेश्वर महादेव मंदिर के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि की आसदी से सचेत किया कि भय अथवा प्रलोभन का दैनिक जीवन में सामना करना पड़ सकता है और ये लोगों को उनके धर्म से दूर ले जा सकते हैं लेकिन धर्म ही खुशी की ओर ले जा सकता है। धर्म हमें जोड़ता है और सही रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए भय या प्रलोभन के प्रभाव में आकर लोगों को अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि हम एक जुट होना जानते हैं और एक जुट होना भी चाहते हैं। हम किसी से लड़ना नहीं चाहत लेकिन आज भी कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो चाहती हैं कि हम अपने आप को बदल बदल दें हमें ऐसी ताकतों से बच कर रहना है संघ प्रमुख ने महाभारत काल का एक दृश्यंत देते हुए कहा कि उस काल में धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास करने वाली ताकतें मौजूद नहीं थीं लेकिन दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड्पने के लिए जो कुछ किया वह अर्थम् था।

आहान करते हुए कहा कि लालच और भय हमें अपनी आस्था से विमुख करते हैं इसीलिए सदगुरु धाम जैसे स्थलों का निर्माण किया गया है। लोगों में धार्मिक चेतना के प्रचार प्रसार हेतु सदगुरु धाम के द्वारा संचालित गतिविधियों एवं कार्यों की सराहना करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि यह संस्थान सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में जाकर आदिवासियों के उत्थान के लिए सामाजिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है। अतीत में जब इस तरह के केंद्रों का अभाव था तब तपस्वी गांव गांव में अपने सत्संग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को धर्म के मार्ग पर ढूढ़ रखते थे लेकिन अब आबादी बढ़ जाने से सदगुरु धाम जैसे केंद्र बन गये हैं जहां समाज के लोग एकत्र हो कर पूजा करते हैं और आध्यात्मिक सत्संग का लाभ प्राप्त करते हैं। यहां उनके कला का अभ्यास करने का अवसर भी मिलता है। संघ प्रमुख ने अपनी इस बात को रेखांकित किया कि सदगुरु धाम जैसे आध्यात्मिक केंद्र लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करते बल्कि उन्हें अपने धर्म पर ढूढ़ रहकर धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे केंद्रों को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है इसी से हमारा कल्याण, राष्ट्र की सेवा और संपूर्ण मानवता का कल्याण सन्निश्चित होगा। भगवत् ने कहा कि धर्म के अभाव में

आचरण करने से समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। यही हमारे राष्ट्र की प्रगति भी सुनिश्चित करता है। भगवत् ने कहा कि हमारा सनातन धर्म किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता इसेलिए सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत को अपनी आध्यात्मिक परंपरा के मार्ग पर सतत अग्रसर रहना चाहिए क्योंकि सारी दुनिया मानती है कि भारत के पास ही इस क्षेत्र में सारी दुनिया का नेतृत्व करने का सामर्थ्य है गौरतलब है कि गुजरात के बलसाड जिले के अंतर्गत धरमपुरा की हरी-भरी पहाड़ियों के मध्य बसा श्री सदगुरु धाम पिछले ढाई दशकों से दक्षिण गुजरात में विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। श्री सदगुरु धाम में निर्मित भगवान भाव भावेश्वर के भव्य मंदिर में दर्शन लाभ हेतु प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है। इस भव्य मंदिर के रजत जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सरसंघचालक मोहन भागवत की उपस्थिति ने इस समारोह को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक यहां शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया जिसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग एक माह तक चलने वाले रजत जयंती समारोह में प्रथम दिवस से ही दूर दूर से श्रद्धालुओं के आगमन का क्रम जारी है।

# आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: अनुभा नहीं

## विवेक रंजन श्रीवास्तव

एआई कोई अजूवा नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क की ही एक उपज है। यह हमारी जीवनशैली को अधिक आरामदायक, सुलभ और प्रभावशाली बना सकती है—बशर्ते हम इसे विवेक और संतुलन के साथ अपार्श्वाण्।

विद्यालय के दिनों में विज्ञानः लाभ और हानि जैसे विषयों पर भाषण, वाद-विवाद और निबंध लिखना आम बात थी। समय बदला, विज्ञान ने रोजमर्रा की जिंदगी में पहले रेडियो, फिर टेलीविजन, मोबाइल और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के रूप में हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए हस्तक्षेप बढ़ाया है। आज एआई हमारी बातचीत, सोच, कामकाज, और यहां तक कि निर्णयों तक को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में एआई के लाभ और

हानि पर विचार करना आवश्यक हो गया है।  
एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वह तकनीक है, जो मशीनों को सीखने, तर्क करने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। वर्ष 2025 में वैश्विक एआई बाजार 244.22 बिलियन तक पहुँच चुका है, और 2031 तक इसके 26.6 लाख की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की संभावना है। यह दर्शाता है कि यह तकनीक केवल भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की भी एक मस्तक वापस्त्रिका है।

सराक वासावकता ह।  
ए.आई. के लाभ  
एआई के उपयोग से दक्षता और उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। यह 24/7 कार्य कर सकती है, मानव त्रुटियों को कम करती है, और डेटा विश्लेषण द्वारा निर्णय लेने में सहायता करती है। स्वास्थ्य, वित्त और निर्माण जैसे क्षेत्रों में यह क्रांतिकारी बदलाव ला रही है।

उदाहरण के लिए, विनिर्माण इकाइयों में एआई संचालित रोबोट उत्पादन को सुव्यवस्थित करते हैं। एआई आधारित चैटबॉट्स ग्राहक सहायता को बेहतर बनाते हैं—नेटफिलक्स की एआई सिफारिशों सालाना 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पहुंचती है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में एआई नई दवाओं की खोज को गति दे रही है—जैसे नवीडिया और फाइज़र का 80 मिलियन का निवेश। यह खतरनाक कार्यों में

मानव जीवन की रक्षा करती है, और पर्यावरणीय मॉडलिंग से जलवायु संकट की समझ को बेहतर बनाती है एआई का सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह हर व्यक्ति के पास जानकारी और समाधान की पहुंच संभव बनाता है। इसके चलते शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के नए द्वारा खल रहे हैं।

कहाँ ऐसी दिशा में न बढ़ जाए, जहाँ उसका नियंत्रण मानव के हाथों से निकल जाए। जनरेटिव एआई कभी-कभी भ्रामक जानकारी भी दे सकता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। यह मानना होगा कि एआई मानव का विकल्प नहीं, सहायक है। हमें इससे भयभीत होने की बजाय इसके लाभों का विवेकपर्ण

ए.आई. के नुकसान  
हर क्रांति की एक कीमत होती है। एआई के आगमन से स्वचालन बढ़ा है, जिससे पारंपरिक नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। एचआर, ग्राहक सेवा, लेखांकन जैसे क्षेत्रों में मानव संसाधनों की आवश्यकता घट रही है एआई को लागू करने की लागत भी ऊँची है—हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और विशेषज्ञों की ज़रूरत छोटे व्यवसायों के लिए चुनौती है। पोपनीयता की बात करें तो एआई विशाल डेटा पर आधारित है, जिससे डेटा उल्लंघन, निगरानी, और एल्पोरिदमिक पक्षपात जैसे खतरे बढ़ जाते हैं।  
एआई का अत्यधिक उपयोग मानवीय संबंधों और संवेदनशीलता को भी प्रभावित कर सकता है—यह भावनाओं को नहीं समझ सकती, जो कि स्वास्थ्य सेवा और मानसिक परामर्श जैसे क्षेत्रों में ज़रूरी हैं।







